

an&gt;

Title: Regarding non-payment of dues by NAFED in Maharashtra.

**श्री राजीव सातव (हिंगोली):** अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के किसानों की बात सदन में रखना चाहता हूँ। चार-पांच महीने पहले महाराष्ट्र में तूर दाल और चने की खरीद का डिसिजन सरकार ने लिया। अब सरकार ने डिसिजन तो लिया, लेकिन 70 से 80 प्रतिशत किसान इससे वंचित रहे। 80 प्रतिशत किसानों का माल भी मार्केट कमेटी में नहीं जा पाया और सरकार की स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ। तब सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि जिन्होंने भी मार्केट कमेटी में रजिस्ट्रेशन किया है, उनको हजार रुपये पर क्विंटल सरकार अनुदान देगी। लेकिन इसके बारे में भी कोई डिसिजन सरकार की तरफ से नहीं आया है।

इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा की जाने आत्महत्याओं का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। जो माल सरकार ने खरीद लिया और जो मार्केट कमेटी एक्ट है, उसके अनुसार 24 घंटे के अंदर किसान को पेमेंट देनी चाहिए। परंतु चार-पांच महीने हो गए, किसानों को न पेमेंट मिल रहा है और न कोई ब्याज मिल रहा है। अतः मेरी मांग है कि उनका पेमेंट मिले और ब्याज भी मिले और जिनका माल लिया नहीं है, उनको हजार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, जो हजार रुपये अनुदान जाहिर किया है, वह देने की कृपा करे। धन्यवाद।

**HON. SPEAKER:** Shrimati Supriya Sule is permitted to associate with the issue raised by Shri Rajeev Satav.